

तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत

प्रलम्बिस के लयि:

[राष्ट्रीय वधकि सेवा प्राधकिरण \(NALSA\)](#) , [राष्ट्रीय लोक अदालत](#) , [वधकि सेवा प्राधकिरण अधनियम, 1987](#) , [गांधीवादी सदिधांत](#) , [वैकल्पकि वविाद समाधान \(ADR \) प्रणाली](#) , [अर्द्ध-न्यायकि नकिया](#) , [स्थायी लोक अदालतें](#)

मेन्स के लयि:

वैकल्पकि वविाद समाधान (ADR) प्रणाली के रूप में लोक अदालत के कार्य और संबंधति चुनौतयिाँ ।

[स्रोत: द हद्वि](#)

चर्चा में क्यौं?

हाल ही में [राष्ट्रीय वधकि सेवा प्राधकिरण \(NALSA\)](#) द्वारा 27 राज्यों/केंद्रशासति प्रदेशों के तालुकों, ज़िलों और उच्च न्यायालयों में वर्ष 2024 की तीसरी [राष्ट्रीय लोक अदालत का](#) आयोजन कया गया ।

- इसका आयोजन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के नेतृत्व में कया गया ।

तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत, 2024 की मुख्य वशिषताएँ कया हैं ?

- नपिटाए गए मामलों की संख्या: तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत, 2024 के दौरान 1.14 करोड़ से अधकि मामलों का नपिटारा कया गया । यह अदालतों में बढ़ते लंबति मामलों को कम करने की दशा में एक बड़ा कदम है ।
- नपिटाए गए मामलों का ववरण: लोक अदालत में नपिटाए गए 1,14,56,529 मामलों में से 94,60,864 मुकदमे-पूर्व मामले थे तथा 19,95,665 मामले वभिन्न अदालतों में लंबति थे ।
- नपिटाए गए मामलों के प्रकार: इन मामलों में समझौता योग्य आपराधकि अपराध , यातायात चालान, राजस्व, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना, चेक का वविचक (dishonor), शर्म वविाद, वैवाहकि वविाद (तलाक के मामलों को छोड़कर) , भूमि अधगिरहण, बौद्धकि संपदा अधिकार और अन्य सविलि मामले शामिल हैं ।
- नपिटान का वतितीय मूल्य: इन मामलों में कुल नपिटान राशकि अनुमानति मूल्य 8,482.08 करोड़ रुप था ।
- सकारात्मक सार्वजनकि प्रतिक्रिया: इस कार्यक्रम में लोगों की भारी भागीदारी देखी गई, जो लोक अदालतों में जनता के मज़बूत वशिवास को दर्शाता है । यह [वधकि सेवा प्राधकिरण अधनियम, 1987](#) और [राष्ट्रीय वधकि सेवा प्राधकिरण \(लोक अदालत\) वनियम, 2009](#) में नरिधारति उद्देश्यों के अनुरूप है ।

लोक अदालत कया है?

- लोक अदालत या जन अदालत: न्यायालय में लंबति या मुकदमे-पूर्व वविादों को समझौते या सौहार्दपूर्ण समाधान के माध्यम से नपिटान हेतु एक वैकल्पकि मंच है ।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर देते हुए कहा है कलोक अदालत न्यायनरिणयन की एक प्राचीन भारतीय प्रणाली है जो आज भी प्रासंगकि है और [गांधीवादी सदिधांतों](#) पर आधारति है ।
 - यह [वैकल्पकि वविाद समाधान \(ADR \) प्रणाली](#) का एक हस्सा है, जसिका उद्देश्य लंबति मामले के संदर्भ में भारतीय न्यायालयों को राहत प्रदान करना है ।
- उद्देश्य: इसका उद्देश्य नयमति न्यायालयों में होने वाली लंबी और महँगी प्रक्रियाओं के बनिा त्वरति न्याय प्रदान करना है ।
 - लोक अदालत में कसी की हार या जीत नहीं होती है, इसमें वविाद समाधान हेतु एक सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाता है ।
- ऐतहासकि वकिस: स्वतंत्र भारत में पहला लोक अदालत शविरि 1982 में गुजरात में आयोजति कया गया था , जसिकी सफलता के बाद इसका

वसितार संपूर्ण देश में किया गया।

- **कानूनी ढाँचा:** प्रारंभ में कानूनी प्राधिकार के बिना एक **स्वैच्छिक संस्था** के रूप में कार्य करते हुए, वधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 द्वारा लोक अदालतों को **वैधानिक दर्जा** प्रदान किया गया।
 - इस अधिनियम द्वारा संस्था को न्यायालय के आदेश के समान प्रभाव वाले अधिकार प्रदान किये गए।
- **आयोजक एजेंसियाँ:** लोक अदालतों का आयोजन नालसा, राज्य वधिक सेवा प्राधिकरण, ज़िला वधिक सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय वधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय वधिक सेवा समिति या तालुक वधिक सेवा समिति द्वारा आवश्यक समझे जाने वाली अवधि और स्थानों पर किया जा सकता है।
- **संरचना:** एक लोक अदालत में आमतौर पर एक न्यायिक अधिकारी (अध्यक्ष), एक वकील और एक सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होते हैं।
- **क्षेत्राधिकार:**
 - लोक अदालत को न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले **लंबित मामलों** और **मुकदमे-पूर्व मामलों** सहित विवादों पर क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
 - यह वैवाहिक विवाद, समझौता योग्य आपराधिक अपराध, श्रम विवाद, बैंक वसूली, आवास और उपभोक्ता शिकायतों जैसे विभिन्न मामलों का निपटारा करता है।
 - लोक अदालत का **गैर-समझौता युक्त अपराधों**, जैसे गंभीर आपराधिक मामलों पर क्षेत्राधिकार नहीं है, क्योंकि इन्हें समझौते के माध्यम से सुलझाया नहीं जा सकता।
- **लोक अदालत को मामले भेजना:** मामले लोक अदालत को भेजे जा सकते हैं, यदि
 - पक्षकार लोक अदालत में विवाद निपटारा हेतु सहमत होते हैं।
 - इनमें से एक पक्षकार द्वारा मामले को लोक अदालत में स्थानांतरित हेतु न्यायालय में आवेदन किया जाता है।
 - मामला लोक अदालत द्वारा संज्ञान लेने योग्य है।
 - **मुकदमा-पूर्व स्थानांतरण:** मुकदमा-पूर्व विवादों को किसी भी पक्ष से आवेदन प्राप्त होने पर स्थानांतरित किया जा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि विवादों का निपटारा न्यायालय में पहुँचाने से पहले ही कर दिया जाए।
- **शक्तियाँ:** लोक अदालत को निम्नलिखित मामलों के संबंध में मुकदमे की सुनवाई करते समय **सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908** के तहत **सिविल न्यायालय** में नहिनी शक्तियाँ प्राप्त होंगी।
 - किसी भी गवाह को बुलाना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना।
 - किसी भी दस्तावेज़ की खोज और जाँच।
 - शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना।
 - न्यायालयों या कार्यालयों से **सार्वजनिक अभिलेखों** या दस्तावेज़ों की मांग करना।
- **लोक अदालत की कार्यवाही:**
 - **स्व-निरधारित प्रक्रिया:** लोक अदालत विवादों के निपटारा हेतु स्वयं की प्रक्रिया निर्दिष्ट कर सकती है, जिससे औपचारिक न्यायालयों की तुलना में प्रक्रिया सरल और अनौपचारिक हो जाती है।
 - **न्यायिक कार्यवाही:** सभी लोक अदालतों की कार्यवाही को **भारतीय दंड संहिता, 1860 (भारतीय न्याय संहिता, 2023)** के तहत न्यायिक कार्यवाही माना जाता है और **दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023)** के तहत सिविल न्यायालय का दर्जा प्राप्त है।
- **नरिणय की बाध्यकारिता:**
 - **सिविल न्यायालय का नरिणय:** लोक अदालत द्वारा दिये गए नरिणयों को सिविल न्यायालय के नरिणय के समान दर्जा प्राप्त होता है, यह अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं।
 - **अपील न किये जाने योग्य:** नरिणयों के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है, इसलिये लोक अदालतों में लंबी अपील संबंधी प्रक्रियाओं की आवश्यकता के बिना विवादों का तीव्र निपटारा किया जा सकता है।



लोक अदालत के क्या लाभ हैं?

- **न्यायालय शुल्क:** लोक अदालत कोई न्यायालय शुल्क नहीं लेती है , बल्कविवाद का नपिटारा लोक अदालत में किया जाता है तो भुगतान की गई शुल्क वापस कर दी जाती है ।
- **प्रक्रिया का सरल होना:** प्रक्रियाएँ सरल हैं और साक्ष्य या सविलि प्रक्रिया के तकनीकी नियमों के प्रावधानों के अधीन नहीं हैं, जिसके कारण ही विवादों का शीघ्र नपिटारा संभव हो पाता है ।
- **प्रत्यक्ष संवाद:** विवाद के पक्षकार अपने वकील के माध्यम से सीधे न्यायाधीश के साथ संवाद कर सकते हैं , जो कि न्यायालयों में संभव नहीं हो पाता है ।
- **अंतिम एवं बाध्यकारी नरिणय:** लोक अदालत द्वारा दिया गया नरिणय पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है जसिसे सविलि न्यायालय का दर्जा प्राप्त होता है तथा यह अपील योग्य नहीं होता है , जसिसे विवादों के अंतिम रूप से नपिटान में देरी नहीं होती ।
- **नमिन समय अवधि:** लोक अदालत शीघ्र समाधान प्रदान करती है, जो औपचारिक लंबी अदालती कार्यवाही से बचाती है ।
- **सामंजस्यपूर्ण नरिणय:** लोक अदालत सहयोग की भावना को बढ़ावा देती है, जहाँ कोई भी पक्ष यह महसूस नहीं करता कि उसने हार मान ली है तथा विवादित पक्षों के बीच संबंध अक्सर बहाल हो जाते हैं ।

लोक अदालत के समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं?

- **भागीदारी की स्वैच्छिक प्रकृति:** जबकि लोक अदालतों का उद्देश्य सौहार्दपूर्ण विवाद का समाधान करना है, दोनों पक्षों को स्वैच्छता से भाग लेने

- **शीघ्र कार्यवाही पर न्यायिक सावधानी:** उच्च न्यायापालिका ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि लोक अदालत की कार्यवाही **सेकसि भी पक्ष के अधिकारों** और नृषिपक्ष प्रतनिधित्व से समझौता नहीं होना चाहिये ।
- **सीमति दायरा:** लोक अदालतों का अधिकार **सविलि और समझौता योग्य आपराधिक मामलों तक ही सीमति है** , जसिसे कानूनी मुद्दों की व्यापक श्रेणी को संबोधति करने की उनकी क्षमता सीमति हो जाती है ।
- **अपील का अभाव:** लोक अदालत का नरिणय अंतमि होता है जसिके नरिणय के बाद अपील नहीं की जा सकती है । यह वादकारी को, खासकर यदवि परणाम से असंतुष्ट है, तो इस तरह की कार्यवाई करने से हतोत्साहित कर सकता है ।
- **पक्षों की अनचिछा:** लोग कभी-कभी **औपचारिक अदालती प्रक्रियाओं पर ही अडे रहते हैं** , क्योंकि उन्हें डर रहता है कि अदालत के बाहर समझौता उनके हतियों को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाएगा ।

- **ADR के मूल सिद्धांतों को मज़बूत करना:** लोक अदालतों को अर्द्ध-न्यायिक निकायों के रूप में विकसित होने के बजाय **सुलह और नपिटान मंच** के रूप में अपनी भूमिका की पुष्टि करनी चाहिये।
 - यह सुनिश्चित करने के लिये न्यायाधीशों और कार्मिकों का उचित प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है ताकि वे औपचारिक न्यायनिरणयन की अपेक्षा **सौहार्दपूर्ण विवाद समाधान को प्राथमिकता दें**।
- **कमज़ोर वर्गों के लिये पहुँच:** एक सक्रिय आउटरीच रणनीति में वधिक सेवा प्राधिकरणों को शामिल किया जा सकता है, जो ग्रामीण और दूर-दराज़ के क्षेत्रों में जाकर **मुकदमा-पूर्व परामर्श प्रदान कर सकते** हैं तथा नागरिकों को यह मार्गदर्शन दे सकते हैं कि लोक अदालतें किस प्रकार उनके विवादों को सुलझाने में मदद कर सकती हैं।
- **तीव्रता बनाम निषेधकता के बारे में चिंताओं का समाधान:** लोक अदालतें एक **स्त्रीकृत प्रणाली अपना सकती हैं**, जहाँ गहन सुनवाई की आवश्यकता वाले विवादों को अधिक समय तक आवंटित किया जाता है, ताकि जल्दबाज़ी में लिये गए निरणयों के जोखिम को रोका जा सके, जिसके अन्यायपूर्ण परिणाम हो सकते हैं।
- **स्थायी लोक अदालतों के क्षेत्राधिकार का विस्तार:** स्थायी लोक अदालतों (जो वर्तमान में सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं तक सीमित हैं) के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करके **छोटे सविल मामलों, उपभोक्ता संबंधी मामलों और पारिवारिक** जैसे मामलों की अधिक श्रेणियों को कवर किया जा सकता है, जिससे न्यायालय में लंबित मामलों को कम करने तथा न्याय तक पहुँच में सुधार करने में मदद मिलेगी।

प्रश्न: भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली के रूप में लोक अदालतों की भूमिका पर चर्चा कीजिये।

- उत्तर: (d)

प्रश्न: लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2009)

1. लोक अदालत द्वारा किया गया अधिनियम सविलि न्यायालय का आदेश (डिक्री) मान लिया जाता है और इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं होती।
2. विवाह-संबंधी/पारिवारिक विवाद लोक अदालत में सम्मिलित नहीं होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर : A

??????:

प्रश्न1. राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में प्रख्यापित अध्यादेश के द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में क्या प्रमुख परिवर्तन किये गए हैं? इससे भारत के विवाद समाधान तंत्र में किस सीमा तक सुधार होगा? चर्चा कीजिये। (2015)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/third-national-lok-adalat>

